एमएसएमई सेक्टर को 76 हजार करोड़ का ऋण दिलाएगी सरकार

लखनऊ। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में एमएसएमई इकाइयों को ऋण मुहैया कराने का लक्ष्य संशोधित किया है। अब इन इकाइयों को 76 हजार करोड़ का ऋण मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अपर मुख्य सचिव एमएसएमई डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक एमएसएमई इकाइयों को 61759 करोड़ रुपये का ऋण मुहैया कराया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ नौ महीने में एमएसएमई इकाइयों को ऋण मुहैया कराना बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में एमएसएमई की साढ़े नौ लाख इकाइयां पंजीकृत हैं। गैर पंजीकृत एमएमएसई इकाइयों की संख्या इससे कई गुना अधिक है। इन इकाइयों ने बहुत कम समय में पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर जैसे उत्पादों को बनाकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाकर मिसाल पेश की। इन इकाइयों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिला है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई इकाइयों में चालू वित्त वर्ष के अंत तक एक करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास है। सीएम योगी आदित्यनाथ एमएसएमई इकाइयों को औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार सृजन के मामले में राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में पेश कर रहे हैं। केंद्रीय बजट में भी इसकी पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 'उद्योग सारथी' लॉन्च कर उद्यमियों को मंच दिया है। एप के जरिए एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्यूरो

सरकार ने जारी किया संशोधित लक्ष्य, अपर मुख्य सचिव ने बताई बड़ी उपलब्धि